वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल

सीएजी रिपोर्ट में राजस्व व्यय, अनुदान, उधारी और बजटीय अनुशासन में कई खामियां उजागर

नवभारत न्यूज

भोपाल, 23 जुलाई. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के राज्य वित्त पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है. रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजटीय अनुशासन, राजस्व व्यय, उधारी, निवेश, अनुदानों के उपयोग और सरकारी खातों के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं.

उप महालेखाकार सुरेश कुमार भोपाल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिशेष तो दर्ज किया, लेकिन राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4.28 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो निर्धारित 4.12 प्रतिशत की सीमा से अधिक है. लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2,004.48 करोड़ के राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाने से वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई. इस समायोजन के बाद राजस्व अधिशेष घटकर मात्र 431.49 करोड़ रह गया.

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल व्यय 3,55,885.58 करोड़ रहा, जबकि कुल बजट प्रावधान 4,06,734.33 करोड़ था. इसके

विधानसभा में पेश हुई नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

बावजूद 50,848.76 करोड़ की बचत हुई, जो कुल प्रावधान का लगभग 12.50 प्रतिशत है. वहीं विभागों ने 20,990.29 करोड़ की राशि समर्पित कर दी, जबकि 29,858.47 करोड़ की राशि बिना उपयोग के व्यपगत हो गई.

लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि बिना पुनर्विनियोजन आदेश के 5,389.42 करोड़ का व्यय किया गया. वित्त विभाग के अंतर्गत 199.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी दर्ज किया गया, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता बताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान विधानसभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक बजट में से 6,253.66 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि 5,921.96 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी आवश्यकता से अधिक पाया गया. इससे बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं.

> राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दी गई राजस्व सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. ऊर्जा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, औद्योगिक नीति तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. सीएजी की यह रिपोर्ट राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण, व्यय नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत देती है. रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु विधानसभा में चर्चा के साथ-साथ शासन-प्रशासन के लिए भी सुधारात्मक कदम उठाने का आधार बन सकते हैं.

राज्य सरकार की उधारी को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है. राज्य का ऋण लगातार बढ़ रहा है और 31 मार्च 2025 तक बकाया देयताओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.32 प्रतिशत तक ऋण की सीमा निर्धारित थी, जबकि राज्य का ऋण इस सीमा के भीतर रहा, लेकिन राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक पाया गया.

रिपोर्ट में सरकारी निवेश की कम प्रतिफल दर को भी रेखांकित किया गया है. राज्य सरकार के निवेश पर वर्ष 2024-25 में मात्र 0.52 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुआ, जबकि सरकार अपने ऋण पर औसतन 6.73 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर रही है. कई सरकारी कंपनियों और वैधानिक निगमों से निवेश के अनुरूप लाभांश भी प्राप्त नहीं हुआ. उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने का मुद्दा भी रिपोर्ट में प्रमुखता से उठाया गया है. 31 मार्च 2025 तक 19,897 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे, जिनकी राशि 22,049.38 करोड़ थी. वहीं तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े 189 व्यक्तिगत जमा खातों में 206.16 करोड़ शेष पाए गए.

प्रमुख तथ्य

- राजकोषीय घाटा 4.28%, लक्ष्य 4.12% से अधिक.
- 2,004.48 करोड़ का राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में दर्शाने पर आपत्ति.
- 50,848.76 करोड़ की बजटीय बचत.
- बिना बजट पुनर्विनियोजन के 5,389.42 करोड़ खर्च.
- 22,049.38 करोड़ के 19,897 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित.
- 189 निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों में 206.16 करोड़ शेष.
- सरकारी निवेश पर केवल 0.52% प्रतिफल, जबकि ऋण पर औसत ब्याज 6.73%.

मनरेगा के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां उजागर, सीएजी की रिपोर्ट

ग्वालियर, 23 जुलाई . भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)की मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन' पर तैयार रिपोर्ट क्रमांक-4 वर्ष 2026 (परफॉर्मेंस ऑडिट-सिविल) को 22 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया.

संविधान के अनुच्छेद-151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत इस रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन का व्यापक परीक्षण किया गया. ऑडिट में योजना निर्माण, धनराशि के आवंटन एवं उपयोग, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति, कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, शिकायत निवारण और पारदर्शिता की समीक्षा की गई.

> ऑडिट में यह भी सामने आया कि चयनित ग्राम पंचायतों ने डेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं किए और न ही रोजगार दिवस आयोजित किए. इसी प्रकार बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं हुई तथा जिला पंचायत स्तर पर श्रम बजट ग्राम पंचायतों की वास्तविक मांग को ध्यान में रखे बिना तैयार किए गए.

महेश प्रसाद श्रीवास्तव उप महालेखाकार प्रथम ग्वालियर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वे एवं डोर-टू-डोर सर्वे नहीं कराए गए, जिससे दिव्यांगों, विधवाओं, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं की पहचान प्रभावी ढंग से नहीं हो सकी. राज्य स्तरीय सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) योजना तैयार नहीं की गई, जबकि चयनित जनपद पंचायतों में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) भी स्थापित नहीं किए गए, जिससे क्षमता निर्माण एवं अभिसरण गतिविधियां प्रभावित हुई.

बस बैक करते समय हेल्पर की पहिए के नीचे दबकर मौत

मुरैना. जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस चालक की कथित लापरवाही के चलते बस को बैक करते समय हेल्पर की पहिए के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार आज सुबह बस स्टैंड पर हेल्पर संजय सिकरवार (51) बस के पीछे सफाई कर रहा था. इसी दौरान चालक ने कथित रूप से बिना ध्यान दिए बस को पीछे करना शुरू कर दिया, जिससे संजय सिकरवार बस के पहिए के नीचे आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर बस को जब्त कर लिया है. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान

भोपाल, 23 जुलाई. मध्यप्रदेश जेल विभाग के जेल मुख्यालय, भोपाल में पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में गरिमामय पिपिंग समारोह आयोजित किया. समारोह में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और सेवा भावना की सराहना की गई. जेल विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता तथा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. वरुण कपूर ने भोपाल केंद्रीय जेल और जेल मुख्यालय के पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्दी पर स्टार एवं लाल निशान लगाकर उन्हें सम्मानित किया. सिविल संवर्ग के पदोन्नत कर्मचारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया.

नौ साल बाद भी स्वयं की छत का सपना अधूरा

- मंछामन मल्टी के 281 हितग्राहीयो के साथ छलावा
- 2017 में शुरू हुआ निर्माण
- गरीबों की मल्टी के भविष्य पर उठने लगे सवाल

नवभारत न्यूज

उज्जैन. एक छोटा सा घर हो अपना, ये सबसे बड़ा सपना हर गरीब परिवार का होता है, नीलगंगा क्षेत्र की मंछामन कॉलोनी के 281 हितग्राहियों के लिए ऐसे आशियाने की उम्मीद पिछले नौ वर्षों से अधूरी है.

वर्ष 2017 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंछामन मल्टी का निर्माण वर्ष 2026 तक भी पूरा नहीं हो सका है. जिन परिवारों ने नगर निगम में अग्रिम राशि जमा कर दी, वे आज भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं.

ठेकेदार बदले, नहीं बदले हालात-निर्माण कार्य के दौरान कई बार ठेकेदार बदल गए. कुछ कंपनियां काम अधूरा छोड़कर चली गईं, नए टेंडर हुए और नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई. वर्तमान में जयपुर की कंपनी पुराने अधूरे निर्माण को पूरा कर रही है. भवनों में रंग-रोगन सहित कई कार्य हो चुके हैं, बावजूद अभी भी पूरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाया है.

बदमाशों ने कर दिया परेशान-हाल ही में मंछामन कॉलोनी में बदमाशों द्वारा निर्माण स्थल पर हमला कर कर्मचारियों से मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद कुछ समय के लिए काम प्रभावित हुआ. इसके बाद नीलगंगा थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन हितग्राहियों का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर उन्हें अपने घर की चाबी कब मिलेगी.

आयुक्त और महापौर भी जुटे-महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्र कई बार निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं. इसके बावजूद कभी भुगतान संबंधी विवाद तो कभी अन्य कारणों से निर्माण कार्य रुक-रुक कर आगे बढ़ता रहा.

एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा-नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम नीलगंगा स्थित कवेलू कारखाना परिसर की जमीन पर भी एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है. ऐसा हुआ तो मंछामन मल्टी के इस प्रोजेक्ट पर भी संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट भी आवासीय और व्यावसायिक है.

बदल सकती है मल्टी की जगह!

अब इस परियोजना को लेकर एक नई चर्चा भी सामने आने लगी है. मंछामन मल्टी के आसपास तेजी से बड़े विकास कार्य हो रहे हैं. यूनिटी मॉल, महाकाल भक्त निवास, चौड़ी सड़कें और अन्य आधुनिक परियोजनाएं इस पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल रही हैं. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या गरीबों की यह मल्टी इसी स्थान पर रहेगी या भविष्य में इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जा सकता है.

समायोजन या राशि वापसी

यदि भविष्य में क्षेत्र की नई विकास योजना के अनुरूप बदलाव किए जाते हैं तो मंछामन मल्टी को लेकर भी नए सिरे से विचार किया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है. यदि कभी परियोजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है तो नगर निगम के सामने 281 हितग्राहियों द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि का समायोजन या वापसी भी बड़ी चुनौती होगी.

एमपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

17 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

60 घंटे से जारी बारिश, वर्षा घाटा घटकर 11 प्रतिशत

भोपाल, 23 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में सक्रिय तीन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पिछले करीब 60 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग ने शुक्रवार को 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश में मानसूनी घाटा घटकर 11 प्रतिशत रह गया है और आने वाले 24 घंटे तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर मानसून द्रोणिका, ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और पूर्व-पश्चिम शियर जोन एक साथ सक्रिय हैं. इन तीनों मौसम प्रणालियों के कारण 20 जुलाई से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में आलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन शामिल हैं.

स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां शुरू

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 जुलाई . मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 15 अगस्त को सुबह 9 बजे लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को गरिमामय, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने पर विशेष जोर दिया गया है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल के निर्देश पर 24 जुलाई से लाल परेड मैदान में परेड का नियमित अभ्यास प्रारंभ होगा. प्रतिदिन सुबह और शाम रिहर्सल आयोजित किए जाएंगे, जबकि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें समारोह की सभी व्यवस्थाओं का अंतिम परीक्षण किया जाएगा. राज्य स्तरीय परेड में महाराष्ट्र पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, विशेष सशस्त्र बल, हॉक फोर्स, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), जिला पुलिस, जेल विभाग, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की टुकड़ियां, स्काउट्स, गाइड्स, शौर्य दल, पुलिस बैंड तथा माउंटेड पुलिस दल सहित कुल 18 प्लाटून भाग लेंगी.

सिंहस्थ 2028 : देशभर से 20 हजार प्रशिक्षित वॉलिंटियर्स होंगे तैयार

उज्जैन, 23 जुलाई. आगामी सिंहस्थ-2028 में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में 20 हजार प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी क्रम में उज्जैन में 'सिंहस्थ सारथी' प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में उज्जैन के पुलिस सामुदायिक भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सिंहस्थ महापर्व के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों तथा एनआरएस सदस्यों को व्यवहारिक, तकनीकी, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी कार्य के लिए प्रशिक्षित करना है. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि उज्जैन जिले में पांच हजार स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा. पहले चरण में लगभग 1,800 स्वयंसेवकों एवं एनआरएस सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जबकि शेष प्रतिभागियों को आगामी चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

नीट पेपर लीक पर कांग्रेस मार्च को पुलिस ने रोका

विशेष संवाददाता

भोपाल. नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा घोटालों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों से देश के लाखों विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है. प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक सहित सभी परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने विभिन्न छात्र आंदोलनों के दौरान विद्यार्थियों पर दर्ज सभी आपराधिक प्रकरण तत्काल वापस लेने तथा संसद में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराने की भी मांग उठाई. सभा को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा. विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. मार्च में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संजीव सक्सेना, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी अंशुल त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, जिला संगठन महासचिव अभिषेक शर्मा, प्रदेश सचिव गुड्डू चौहान, राजकुमार सिंह,बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र शामिल रहे.

एसीई की बेनामी संपत्ति जांच में 17 करोड़ का आंकड़ा पार

- लोकायुक्त ने खंगाले 25 बैंक खाते
- फर्मों के खातों में मिले 62 लाख रुपए

नव भारत न्यूज

इंदौर, 23 जुलाई. एडिशनल चीफ इंजीनियर (एसीई) शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की जांच आगे बढ़ने के साथ संपत्तियों का आंकड़ा बढ़कर 17.12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.

पहले चरण की कार्रवाई में सामने आई संपत्तियों के बाद अब जांच एजेंसी ने बैंक खातों, एफडी, निवेश और मुरैना स्थित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है. लोकायुक्त पुलिस की जांच में सेमिल, उनके परिवार और उनसे जुड़ी फर्मों के नाम से संचालित 25 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है. इनमें एसबीआई और आईडीबीआई बैंक के खाते शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये खाते शिवराम सेमिल, उनकी पत्नी रामबेटी, बेटे सौरभ, बहू सुनीता और संबंधित फर्मों के नाम पर संचालित थे.

जांच में मुरैना स्थित संपत्तियां भी सामने आई हैं. यहां करीब 50 लाख रुपए कीमत का मकान मिला है, जिसमें रखे घरेलू सामान का मूल्यांकन करीब 7.51 लाख रुपए किया है. इसके अलावा 20 बाय 40 फीट का प्लॉट और करीब सवा बीघा कृषि भूमि होने की जानकारी मिली है. इन संपत्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंजीयन विभाग से कराया जा रहा है. लोकायुक्त सूत्रों ने यह भी बताया कि सेमिल, उनके परिवार और संबंधित फर्मों के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है. आयकर विभाग से परिवार के सदस्यों के रिटर्न की जानकारी मांगी गई है. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश की जानकारी के लिए सेबी को भी पत्र भेजा है. लोकायुक्त अधिकारी का कहना है कि जांच अभी जारी है, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद संपत्ति के अंतिम मूल्यांकन और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

निर्देश | श्योपुर-सिंगरौली मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं की समीक्षा

आवश्यक कार्य समय सीमा पर पूरा करें : शुक्ल

भोपाल, 23 जुलाई . उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने श्योपुर और सिंगरौली शासकीय मेडिकल कॉलेजों की शैक्षणिक एवं चिकित्सीय व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी आवश्यक कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने फैकल्टी की उपलब्धता, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, आउटसोर्स स्टाफ और अन्य आधारभूत सुविधाओं की प्रगति का जायजा लिया.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों मेडिकल कॉलेजों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा उपकरणों और संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान सहित सभी व्यवस्थाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए.

> शुक्ल ने कहा कि श्योपुर और सिंगरौली जैसे आकांक्षी क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कॉलेज स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा देने के साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेंगे. बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

दतिया उपचुनाव : मंत्री सिंधिया आज करेंगे सभा

ग्वालियर/दतिया, 23 जुलाई . केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को ग्वालियर एवं दतिया जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे. अपने इस दौरे के दौरान सिंधिया मां पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन-पूजन करेंगे.

दतिया उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में आशुतोष तिवारी के चुनावी अभियान को गति देंगे. वे दतिया में जनसंपर्क अभियान तथा बड़ौनी में जनसभा के माध्यम से जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान का आह्वान करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंधिया प्रात: 9:20 बजे नई दिल्ली से

प्रस्थान कर 10:50 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से वे सड़क मार्ग द्वारा दतिया के लिए रवाना होंगे. दोपहर 1 बजे वे मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन एवं पूजन करेंगे. इसके पश्चात दोपहर 2:15 बजे दतिया के बड़ौनी में आयोजित जनसंपर्क अभियान एवं जनसभा में भाग लेंगे.

पेज एक का शेष

लवकुश फ्लाईओवर की एक लेन शुरू...

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यात्रा समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और जाम से राहत मिलेगी। दूसरी लेन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इस अवसर पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग, साहस और बलिदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समान अवसर और समान कानून के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है .जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60